(ग) देश में आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक कुल कितने लघु उद्योग एकक कार्यरत हो जाने का अनुमान है और सातवीं पंचवर्षीय योजना की तुलना में यह संख्या कितनी अधिक होगी?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम): (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है किन्तु सातवीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक कुल 20.82 लाख मौजूद एककों की तुलना में आठवीं पंचवर्षीय योजना के पहले दो वर्षों अर्थात् 1992-93 और 1993-94 के दौरान लघु औद्योगिक एककों की संख्या क्रमशः 22.35 लाख और 23.84 लाख थी।

Moll signed for setting up paper and sugar project in Punjab

4783. SHRI IQBAL SINGH: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government have signed any Memorandum of Understanding to set up a project of producing paper and sugar in the State of Punjab during the last two years;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the steps taken by Government in this respect?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OR INDUSTRY (SMT. KRISHNA SAHI): (a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise.

लघु और कुटीर उद्योगों के लिए सुविधाएं

4784. श्री इकबाल सिंह: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) भारत में लघु और कुटीर उद्योगों के विकास के लिए सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं और रियायतों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने लघु उद्योग क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और नयी उदारीकरण नीति के अंतर्गत विदेशी कंपनियों से प्रतिद्वन्दिता करने के लिए उन्हें संरक्षण प्रदान करने की कोई योजना बनाई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम): (क) भारत की अर्थव्यवस्था के विकास में लघु और कुटीर उद्योग क्षेत्र की भूमिका को सरकार ने स्वीकार किया है। अतः इन उद्योगों के विकास को औद्योगिक विकास के कार्यक्रमों में उच्च प्राथमिकता मिल रही है और इस क्षेत्र को सहायता उपलब्ध कराना सरकार की औद्योगिक नीति की एक मुख्य विशेषता रही है।

सरकार ने अनेक उपाय किये हैं जिनमें संस्थागत सहायता और रियायती वित्त जैसे प्रोत्साहन व रियायतें, उत्पाद शुल्क के लाभ, अनन्य उत्पादन के लिए मदों का आरक्षण, लघु एककों से खरीददारी के लिए मदों का आरक्षण, तकनीकि परामर्श सेवाएं, परीक्षण सुविधाएं, सामान्य सुविधा सेवाएं और आधारभूत सुविधाएं शामिल हैं। राज्य सरकारें भी इस क्षेत्र को सुविधाएं और प्रोत्साहन देती हैं।

(ख) से (ग) लघु क्षेत्र में अनन्य विनिर्माण के लिए उत्पादों का आरक्षण प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण देने और उत्पाद शुल्क में छूट देने के लिए सरकार की नीति जारी है। बड़े और मझौले एककों द्वारा आरक्षित मदों का विनिर्माण करने के लिए 75 प्रतिशत निर्यात दायित्व और स्वदेशी तथा विदेशी दोनों प्रकार के अन्य औद्योगिक उपक्रमों द्वारा लघु औद्योगिक क्षेत्र की इक्विटी में 24 प्रतिशत से अधिक की भागीदारी न करने की अनुमति देने से सम्बन्धित प्रावधानों का उद्देश्य लघु क्षेत्रों के हितों की रक्षा करना है।

Off loading of PSU shares

4785. SHRI VIREN J. SHAH:
SHRI PRAMOD MAHAJAN:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the report published in the Times of India' of January 2, 1995 under the caption, "PSU blue chips find way to grey market";

(b) If so, what are the facts .and necessary details in this regard;

(c) what were the recommendations of the Jankiraman Committee which looked

into the Security Scam about the off-loading of PSU shares before their listing on the stock exchanges; and

(d) what steps Government have taken or propose to take to stop this practice of unofficial trading?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SMT. KRISHNA SAHI): (a) to (d) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Setting up of heavy industries In Gujarat

4786. SHRI ANANTRAY DEVSHANKER DAVE: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the State Government of Gujarat has submitted any new proposal for setting up of heavy industries in the State;

(b) if so, the details thereof and the latest position of the said proposal; and

(c) the places where these industries are to be set up together with the details of the expenditure involved therein?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SMT. KRISHNA SAHI): (a) Six applications were received during 1st January 1992 to 31st March, 1995 under the provisions of Industries (Development & Regulation) Act from undertakings belonging to State Public Sector and State Industrial Development Corporations for setting up of industries in Gujarat.

(b) and (c) The above applications were for taking up manufacture of various items pertaining to Scheduled Industries viz. Chemicals, Paper & Pulp, Drugs & Pharmaceuticals and Fuel. The proposed locations were Bharuch and Baroda/Vadodara districts. The proposed investment in fixed assets (i.e. land, building, plant and machinery) in respect of these applications was Rs. 47077 Lakhs. Against the above applications, four Letters of Intent have been granted and two applications have been rejected.

सरकारी क्षेत्र में सीमेंट का उत्पादन

4787. **श्री अनंतराम जायसवाल:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकारी क्षेत्र में सीमेंट की उत्पादन करने वाले कितने एकक हैं और उनमें से कितने काम कर रहे हैं और प्रत्येक की मासिक उत्पादन क्षमता क्या है;

(ख) क्या देश में उत्पादित सीमेंट का बहुत बड़ा हिस्सा अन्य देशों को निर्यात कर दिया जाता है और यदि हां, तो वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान सीमेंट का कितनी मात्रा में किन-किन देशों को निर्यात किया गया और इस निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(ग) 1995-96 के दौरान कितनी मात्रा में सीमेंट का निर्यात करने का लक्ष्य है और इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित होने की संभावना है; और

(घ) क्या यह सच है कि सरकार ने निकट भविष्य में सीमेंट के मूल्य बढ़ाने का निर्णय किया है और यदि हां, तो किन परिस्थितियों के तहत ऐसा निर्णय किया गया और इस निर्णय के पीछे क्या-क्या कारण हैं और मूल्य वृद्धि के फलस्वरूप सीमेंट का प्रति बैग मूल्य क्या होगा और इसका आम जनता द्वारा मकान बनाए जाने की गतिविधियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के एक उपक्रम सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया के स्वामित्व में 11 संयंत्र हैं जिनके ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिये गये हैं। (नीचे देखिये)। ये सभी 11 एकक काम कर रहे हैं।

(ख) जी, नहीं। इस समय सीमेंट/क्लिंकर के कुल उत्पादन के थोड़े से हिस्से का निर्यात किया जा रहा है। 1993-94 और 1994-95 में निर्यात के देशवार ब्यौरे दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है (नीचे देखिये) जैसा कि वाणिज्य मंत्रालय द्वारा बताया गया है अनुमानित विदेशी मुद्रा में आय 1993-94 में 286.5 करोड़ रुपये और 1994-95 (फरवरी तक) में 411.2 करोड़ रुपये थी।

(ग) वर्ष 1995-96 के लिये कोई विशिष्ट निर्यात लक्ष्य निधारित नहीं किया गया है।

(घ) 1.3.1989 से सीमेंट के मूल्य और वितरण से नियंत्रण हटा दिया गया है अतः सरकार द्वारा सीमेंट के मूल्यों में वृद्धि करने का प्रश्न ही नहीं उठता।